प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
19.06.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

प्रधानमंत्री–विकसित भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2 हजार 4 सौ करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देशभर में 15 लाख से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं। ये राशि लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। विकसित भारत रोजगार योजना अगस्त 2025 से शुरू हुई थी और अब तक देश भर में 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्य बल में शामिल किया गया है जिसमें लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जा रहा है जहां प्रदेश के 6 हजार 99 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री–स्वास्थय विभाग

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता प्रदान करेगी। शिमला में स्वास्थ्य विभाग की एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अवसंरचना व सेवाओं को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले दिनों में वे खुद विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा कर डॉक्टरों के साथ संवाद करेंगे और आधुनिकीकरण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा मशीनरी व उपकरणों की खरीद पर लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ज़िलों में मैडिकल कॉलेज नहीं है, वहां क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों की सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है।

अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के हर नागरिक के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को पाने का एक उपयुक्त माध्यम बनाया जाना समय की मांग है। नई दिल्ली में आज 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन–2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसे आज की जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थित रूप से अपडेट किया गया है। अमित शाह ने कहा कि ऐसे कई जटिल मामले हैं जिन्हें इस प्रणाली के माध्यम से सुलझाने में मदद मिली है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के हर चरण, जांच और अभियोजन से लेकर अंतिम सजा तक तकनीक को प्रभावी ढंग से शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

एचआरटीसी

राज्य पथ परिवहन निगम के चालको व परिचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ये कर्मचारी प्रदेश के अनेक स्थानों पर अपनी मांगों को लेकर गेट मिटिंग कर रहे हैं। नाहन में भी इन कर्मचारियों ने गेट मिटिंग कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एचआरटीसी चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले लगभग 75 महीनों से उन्हें ओवर टाईम का भुगतान नहीं हुआ है और मैडिकल भत्तों के रूप में भी लगभग 20 करोड़ रुपये सरकार के पास बकाया है। संघ ने राज्य सरकार व निगम प्रबंधन को कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिए 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है।

विकसित भारत–जीरामजी

केंद्र सरकार पहली जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी–जीरामजी अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए देश भर में सौ से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों की तैनाती करेगी। ये क्षेत्रीय अधिकारी राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और जमीनी स्तर के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। इससे कार्यान्वयन आवश्यकताओं को समझा जा सकेगा और क्षमता निर्माण प्रयासों में सहयोग दिया जा सकेगा।

.....